कृषिमित् कृषस्व-खेती ही करो

भारतीय किसान संघ

(सो रजि अधि के अंतर्गत पंजीकृत गैर सरकारी संगठन : पं क्र 758/2001-2002)
पंजीकृत कार्यालय : उत्तरांचल उत्थान परिषद, सेवा निकेतन, हरिद्वार रोड, पो -नेहरू ग्राम, देहरादून (उत्तराखण्ड)
प्रशासनिक कार्यालय : 43, पं. दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002
www.kisansangh.org, E-mail- bkscentraloffice@gmail.com दूरभाष : 011-23210048

Date: 20.10.2016, New Delhi

Press Release

Ban GM Sarson and Scan the GEAC

Mustard used in India as leafy vegetable, edible oil, for massage, medicine and even as fertilizer and pest control and animal feed as well. Now a day GEAC (genetic engineering appraisal committee) is in a hurry to give permission to GM mustard for commercial cultivation. This GM mustard testing application was rejected by the same GEAC in 2002. What again happened that now the GEAC is in hurry to give permission and under whose pressure.? The producer scientist first declared that it is High yielding .When they caught red handed that no testing was done for high yielding-now talking for HT (herbicide resistance). The chemical usually used in herbicide tolerant was glyphosate, later declared, after the use of more than decades that it is Carcinogenic by the WHO. Now in this GM mustard HT hybrid the chemical to be used will be Glufosinate, as said by the scientist and the related MNC. Whether this chemical is carcinogenic or not is yet to be tested, yet to be assed, until that many years the GM mustard has to go through serious tests with all transparency, because it deals with long term human health concerns. If the entire GM technology is against Chemical farming, then what is this HT GM technology which is entirely depends on huge chemical spraying that is mandatory with this technology. **Who knows what this chemical will create-cancer/male sterility/infertility/what?** *Nobody knows.* GM propagaters have announced that this technology will reduce chemical spraying. What is this? This GM mustard will mandatorily use heavy amount of spraying. To whom they are making fools.?

The first GM crop was cultivated in India was BT cotton in 2002. It failed in 2005.2nd stage Bt cotton introduced with more toxin releasing bacteria gene in 2006. It also failed in 2009-10. This GM technology already failed. Why GEAC is so interested in introducing it in food crops is a big question. During myth regime of Bt cotton this GEAC did not allow our seed testing laboratories to test the accuracy and efficacy of these GM (Bt) seeds for some unknown reasons. It is a known fact that some people advocating for GM food crop wrongfully not knowing that neither it is high yielding, nor it is sustainable. It proposes monoculture that enhances malnutrition and risks seed sovereignty of our country. The predatory pricing of these seeds is another issue that was tried to solve by Agriculture ministry, is now under

threat from unknown sources, yet to be identified. This technology is altogether a failed one, not correctable, not reversible and not controllable as it is a living technology. Who will take the responsibility if something goes wrong (it is proven fact that it is wrong), neither the GEAC nor the developer is talking.

The parliamentary standing committee is against it. The technical expert committee of Supreme Court as well as, non manageable independent scientists are against it Government of India put a moratorium on this technology still the so powerful GEAC is pushing this -really this is the mystry to be explored. Neither it is high yielding nor does it give more oil content. Report are there that where ever GM Mustard Cultivated it did one thing that it has abolished the entire polulation of honey bee from that area. The result of Bt cotton experience was the huge suffering of farmers, huge public money as compensation to the farmers (in 2014 in Karnataka there was a loss 235 cr. and this year only in raichur district the loss is 278 cr.) and the company moving with its business- free, without any responsibility. Karnataka Government is burning the entire failed crop to eradicate the left over pink bollworm above and under the soil.

The entire relevancy of GM mustard is under question. Why should we need this GM mustard without any need for that? When we have plenty of mustard varieties performing much better ahead of the claimed one of GM mustard. And the GEAC is also under scanner of doubts that why it did not allow our designated seed testing laboratories to test the BT cotton seeds along with its lunching. Suspiciously acting in favour of some spurious MNCs for unknown reasons. So, it became priority to examine the role of GEAC in relation to allowing GM crop against the moratorium of Govt. of India and against the report of Technical expert committee of Hon Supreme Court and against the large number of doubts about its origin and genesis.

That's why Bharatiya Kisan Sangh appeals to ***ban the introduction of GM mustard*** with immediate effect and to have and transparent ***internal enquiry about the sole existence of function of GEAC*** and its mandatory relevance with the safety assessment of any introduction.

कृषिमित् कृषस्व-खेती ही करो

भारतीय किसान संघ

(सो.रजि. अधि. के अंतर्गत पंजीकृत गैर सरकारी संगठन पं. क्र. 758/2001-2002)

पंजीकृत कार्यालय : उत्तरांचल उत्थान परिषद, सेवा निकेतन, हरिद्वार रोड, पो. नेहरू ग्राम, देहरादून (उत्तराखण्ड)

प्रशासनिक कार्यालय : 43, पं. दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002

www.kisansangh.org, E-mail- bkscentraloffice@gmail.com दूरभाष : 011-23210048

दिनांक : 20.10.2016, नई दिल्ली

प्रेस विज्ञप्ति :-

जीएम सरसों को बैन करो
जी.ई.ए.सी. की जांच करो

सरसों एक खाद्य सामग्री है। सरसों का साग व तेल, भोजन, औषधि, मालिश आदि के रूप में सीधा मानव के लिए काम में आता है। सरसों की खली पशु आहार में पौष्टिक तत्वों की पूर्ति करती है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जी.ई.ए.सी.) जी. एम. सरसों को अनुमति देने की जल्दबाजी में है। सरसों के बीज में आनुवांशिक परिवर्तन करने वाले वैज्ञानिकों एवं इसकी वकालत करने वालों ने सर्वप्रथम जानकारी दी कि यह पुर्लिंग नपुंसकता वाली किस्म है। बाद में कहा गया कि यह अधिक उपज देने वाली किस्म है। परन्तु वास्तव में जब यह पता चला कि अधिक उपज संबंधी परीक्षण भी नहीं हुआ है, तब कहा गया कि यह तो हर्बीसाइट टोलरेंट किस्म है।

फसलों में रसायनों का प्रयोग बंद करने के लिए जी.एम. तकनीक को विकल्प बतलाया गया, परन्तु हर्बीसाइट टोलरेंस का तात्पर्य तो हुआ कि खरपतवार नाशक रसायन छिड़कने से इस जी. एम. सरसों पौधे को छोड़कर सभी वनस्पति नष्ट हो जाएंगी, अर्थात जैव विविधता को नष्ट करने वाला सिद्ध होगा।

ऐसा प्रचारित करना बड़ा संकट खड़ा करता है-

1. क्या यह अधिक पैदावार देता है- उत्तर कुछ नहीं।
2. क्या यह पुरुष नपुंसकता को बढ़ाएगा- उत्तर कुछ नहीं।
3. रसायनों का प्रयोग कम करने वाला है- उत्तर नहीं।

■ पहले से ही संसद की स्थायी समिति ने जी. एम. फसलों पर रोक के लिए निर्देशित किया है। ■ सुप्रीम कोर्ट की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने भी इसके खिलाफ निर्णय दिया था। ■ वर्ष 2010 में भारत सरकार ने इसके ऊपर रोक लगाई थी, फिर भी इन सबके ऊपर जी.ई.ए.सी. यह निर्णय कैसे ले रही है, यहां एक बड़ा प्रश्न है।

स्वयं जी.ई.ए.सी. ने अपने ऊपर प्रश्नचिन्ह लगा दिया, जब बिना अनुमति के बी. टी. कपास की देश में खेती चालू कर दी। बाद में अनुमति दी गई। मगर बी. टी. कपास के बीज की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए अपने देश के बीज परीक्षण केंद्रों को अनुमति नहीं दी गई, क्यों? बी. टी. कपास के विफल होने के सत्य को कंपनी, सरकार और वैज्ञानिक भी मान चुके हैं। बी. टी. कपास से पीड़ित किसानों को इसकी हानि की भरपाई सरकारें अपने खजानों से कर रही है। कंपनी निश्चिंत घूम रही है, जी.ई.ए.सी.

चुप बैठी है। महाराष्ट्र में हरेक साल कपास के किसानों को दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की क्षतिपूर्ति की जा रही है। 2014 में कर्नाटक में किसानों का 235 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। सरकार ने अपने खजाने से 35 करोड़ रुपये की भरपाई की। किसान करें तो क्या करें, कंपनी मौज कर रही है। इसी साल वहीं कर्नाटक के राईचूर जिले में कपास के नुकसान का 278 करोड़ का आंकलन हुआ। सरकार और किसानों ने मिलकर फसल को जलाया। कहीं पिंक वोल्वार्म न जिंदा रह जावें, इसीलिए कपास की खेती को आग के हवाले कर दिया गया। कंपनी मुक्त है और जी.ई.ए.सी. सुस्त।

अब जी. एम. सरसों का साग खाने से क्या होगा, किसी को पता नहीं। जी. एम. सरसों के कारण मधुमक्खियों के छत्ते समाप्त हो जाएंगे, यह निश्चित है। पुरुष नपुंसकता का जीन किसके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, उसके ऊपर कोई परीक्षण नहीं हुआ है। फिर भी जी.ई.ए.सी. बोल रहा है-यह सुरक्षित है। जबकि भारत के पौष्टिक आहार विज्ञानी बोलते हैं कि इसकी सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं दे सकता। जी. एम. सरसों के वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि अगर अनुमति नहीं मिलेगी तो इस पर जो खर्चा हुआ है, उसका क्या होगा?

जी. एम. तकनीक अभी तक असफल है। इसके ऊपर और शोध जारी रहे, जिनको करना है वो करें, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मगर कुछ वैज्ञानिक और जी.ई.ए.सी. जनता को जहर खिलाने पर क्यों तुले हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है।

यह तकनीक अपरिवर्तनीय है, असंशोधनीय, प्रत्याहार रहित है। इसके साथ यह तकनीक असफल भी है। इसीलिए हम इसके खिलाफ हैं। जब तक इन सभी प्रश्नों के उत्तर न मिल जाए, तब तक विरोध जारी रहेगा। भारतीय किसान संघ की यह भी मांग है कि तत्काल प्रभाव से जी. एम. सरसों को रोका जाए तथा जी.ई.ए.सी. की कार्य प्रणाली की जांच हो।

जहर नहीं जैविक चाहिए,
जीएम नहीं जिंदगी चाहिए।